

दैनिक

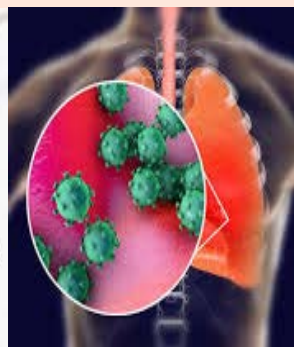
रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र में एच3एन2 की दहशत

3 मरीजों की मौत की खबरों पर सरकार ने जारी किया बयान



मुंबई : महाराष्ट्र में कुल 3 सस्पेक्ट एच3एन2 से मौत का मामला सामने आया था. ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद पता चला है की 2 मौत एच3एन2 वायरस से नहीं हुई है. एक सस्पेक्ट मामला अहमदनगर का है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट अभी आना बाकी है. यानी की महाराष्ट्र में अभी सिर्फ एक मौत सस्पेक्ट एच3एन2 से बताई जाई जा रही है.

महाराष्ट्र में एच3एन2 मामलों में वृद्धि

राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार,

महाराष्ट्र में एच3एन2 मामलों में 200 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. इस साल 1 जनवरी से 15 मार्च तक इंप्लूएजा के 58 मामले आए थे, हालांकि गुरुवार को कुल आंकड़ा 119 हो गया. अचानक से बढ़ रहे मामलों को लेकर महाराष्ट्र की सरकार अलर्ट है. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

डॉक्टरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला और नागरिक स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे रिपोर्ट करें, संदिग्धों की पहचान

अस्पताल में कितने मरीज हैं भर्ती

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को एच3एन2 के सभी मामलों की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब तक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में 2,66,912 संदिग्ध मामले आए हैं, जिनमें से 324 एच1एन1 और 119 मामले एच3एन2 के मिले हैं. वर्तमान में, पूरे महाराष्ट्र में वायरल बीमारियों के कारण 73 मरीज भर्ती हैं.

करें और आइसोलेशन वार्ड तैयार करें और तत्काल इलाज शुरू करें. इन्फ्लूएजा के मामलों को संभालने के लिए डॉक्टरों को 17 मार्च को प्रशिक्षित किया जाएगा. महाराष्ट्र में अचानक से बढ़ रहे एच3एन2 के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार से लेकर तमाम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है.

उच्च न्यायालय का शिंदे सरकार से सवाल

गैरकानूनी हड़तालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?



मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के सरकारों कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार से शुक्रवार को पूछा कि गैरकानूनी हड़तालों के 'खतरों को रोकने के लिए वह क्या कर रही है? अदालत ने कहा कि इन सब से आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.वी. गंगपुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मारों की खंडपीठ अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर करते हुए यह बात कही.

याचिका में शिक्षण और चिकित्सकीय क्षेत्र के कर्मचारियों सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को तत्काल वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग को लेकर राज्य के लाखों सरकारी

कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे राज्य में प्रशासनिक कामकाज और कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। महाधिवक्ता बरिंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि हड़ताल 'अवैध है और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि हड़ताल के कारण किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। पीठ ने सरकार से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा कि वह बुनियादी सुविधाओं व आवश्यक सेवाओं तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

अदालत ने कहा, 'हमें चिंता है आम नागरिक आवश्यक सेवाओं से वंचित न रह जाएं। आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि इस खतरे को रोकने के लिए राज्य क्या कदम उठा रहा है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है। अदालत ने मामले को 23 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन सरकार का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उचित कार्रवाई करे ताकि किसी को परेशानी न हो।

महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा, बस से सफर में 50% की छूट



मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सुबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। आज से ही सरकार ने ये सुविधा लागू कर दी है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्री करेंगी। वहां उनको उस तय यात्रा के किराए में 50 प्रतिशत की राहत

मिलेगी। परिवहन निगम के अनुसार, महिलाओं को यह लाभ देने के लिए राज्य की सरकार एमएसआरटीसी को रियायत राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। बता दें कि इसी साल नौ मार्च को राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया था। जिसमें उन्होंने सार्वजनिक परिवहन निकाय की बसों में सभी महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की थी।

सहकारी बैंक भर्ती में शिंदे सरकार को झटका 'दखलअंदाजी' बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया फैसला

मुंबई : सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने 3 मार्च के अपने आदेश में शिंदे के फैसले को पूरी तरह से अनुचित और कानून के अधिकार के बिना करार दिया। यह आदेश चंद्रपुर



डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और संतोषसिंह रावत नाम के एक व्यवसायी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया। बता दें, रावत को शिंदे के फैसले का विरोध करते हुए बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। याचिका के मुताबिक, स्थानीय

नेताओं के इशारे पर सीएम का आदेश पारित किया गया था और इसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बैंक कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिससे 93 शाखाओं को चलाना असंभव हो गया है। सीएम ने नवंबर 2022 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

महाराष्ट्र: पालघर में 10 लाख रुपये से अधिक के मादक पदार्थजब्त, दोव्यक्तिगिरफ्तार



पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की 'मेफेड्रोन और चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ निरीक्षक साहाराज रानावरे ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और आरोपी को बुधवार को नालासोपारा इलाके के चंदन नाका से गिरफ्तार कर लिया।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

लोकतंत्र और नैतिकता

यह विडंबना ही है कि सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते सरकार बनाने-गिराने का जो खेल हाल के दशकों में राज्यों में नजर आया, उसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठे हैं। कहीं न इस पद की गरिमा के विपरीत राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़

सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर व्यवहार करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रवृत्ति हाल में ही उभरी हो, आजादी के कुछ दशकों के बाद से ही यह खेल निरंतर जारी रहा है। राज्य में विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिये इस पद का दुरुपयोग कांग्रेस से लेकर राजग सरकारों के दौर में होता रहा है। इस संकट को महसूस करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र प्रकरण में तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी की कि सत्तारूढ़ पार्टी में असंतोष की स्थिति में राज्यपाल का बहुमत साबित करने को कहना अनुचित है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल में यदि मतभेद होने पर बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता है तो निर्वाचित सरकार के अस्तित्व पर संकट पैदा हो सकता है। यानी इसमें राज्यपाल की भूमिका हस्तक्षेप करने वाली नहीं होनी चाहिए। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह लोकतंत्र का प्रहसन ही होगा। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने यह टिप्पणी बीते साल अविभाजित शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद राज्य में पैदा राजनीतिक संकट के बाबत की। तब भी राज्यपाल की भूमिका को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किये थे। दरअसल, कोर्ट ने इस संकट के बाबत दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ही यह तल्ख टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा व शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कालांतर सत्ता में बंटवारे को लेकर दोनों दल अलग हो गये थे और कम विधायकों वाली शिवसेना ने कुछ विपक्षी दलों के समर्थन से सरकार बना ली थी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि राज्य में शिवसेना की सरकार बनने के बाद भाजपा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से शिवसेना सरकार पर हमलावर रही है। इस काम में जहां तमाम विवादों में सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप लगे, वहीं राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते रहे। केंद्र की सत्ता में होने का लाभ राज्य भाजपा को मिला। राजग के सबसे पुराने सहयोगियों में रहे शिवसेना व भाजपा में कटुता इस हद तक जा पहुंची कि बात सरकार को गिराने तक में परोक्ष भूमिका तक पहुंच गई। यह राजनीतिक विद्रूपता ही है कि किसी पार्टी के बैनर तले चुनकर आये जनप्रतिनिधि सत्ता व अन्य सुविधाओं के प्रलोभन में पाला बदलकर मूल दल के विरोधियों के साथ बगलगीर हो जाते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार भाजपा के समर्थन से ही अस्तित्व में बनी हुई है। सही मायनों में शीर्ष अदालत ने इन्हीं राजनीतिक विद्रूपताओं की ओर इशारा करते हुए कहा है कि राज्यपाल द्वारा किसी राजनीतिक दल में असंतोष के चलते बहुमत साबित करने को कहना अपरोक्ष रूप से सरकार को अस्थिर करना ही है। कुल मिलाकर कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका के नैतिक पक्ष को उजागर करने के साथ ही इस पद की गरिमा को बनाये रखने का संदेश दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कई वाजिब कारण मौजूद थे, जिसके चलते राज्यपाल ने उद्भव सरकार को सदन में बहुमत साबित करने को कहा था।

editor@rookthoklekaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने के लिए साथ आएं शहबाज और इमरान! दोनों की ओर से आया बड़ा बयान

इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने गुरुवार को एक घोषणा की कि वह देश के उत्थान, हित और लोकतंत्र के लिए किसी से भी बात करने और कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार है। खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग का आग्रह किया।

‘चुनौतियों को हल करने के लिए बातचीत की जरूरत’

पीएम शहबाज द्वारा पीटीआई नेता को एक जैतून शाखा की पेशकश करने के एक दिन बाद दोनों नेताओं की टिप्पणी आई, जिसमें जोर दिया



गया कि देश को निरंतर राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए सभी राजनीतिक समूहों को बातचीत के लिए एक साथ आने की आवश्यकता होगी।

पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने किया ट्वीट

आपको बता दें, फिलहाल इमरान कई कानूनी मामलों का सामना कर

रहे हैं, गिरफ्तारों से बच रहे हैं और वर्तमान में अपने जमाना पार्क वाले घर में हजारों समर्थकों के साथ छिपाया हुआ है। इमरान ने ट्वीट किया, ‘मैं पाकिस्तान के उत्थान, हित और लोकतंत्र के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटूंगा। इस संबंध में, मैं किसी से भी बात करने और इसके लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ।’

अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में डिजाइनर अनीक्षा को 21 मार्च तक

पुलिस हिरासत

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गुरुवार को डिजाइनर अनीक्षा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आरोपी अनीक्षा जयसिंघानी को अब आगामी 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

जानकारी दें कि, अमृता फडणवीस ने अपने फोन पर धमकी भरे कॉल और संदेश प्राप्त करने के बाद मुंबई स्थित डिजाइनर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं खुद अमृता फडणवीस ने अनीक्षा पर उन्हें एक करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

वानखेड़े स्टेडियम में फैस को मिलेगा डबल धमाल, ‘भोला’ के प्रमोशन के लिए अजय देवगन बनेंगे मैच का हिस्सा



मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। अजय इस दौरान मैच को एंजॉय करते हुए अपनी अपकमिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म ‘भोला’ का प्रमोशन भी करने वाले हैं।

फिल्म रिलीज के लिए एक्साइटिड हैं फैस

जब से ‘भोला’ फिल्म से अजय देवगन का पहला लुक सामने आया है। तब से फैस में फिल्म को लेकर क्रेज बना हुआ था। वहीं फिल्म के ट्रेलर ने उनकी एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल अजय की ये फिल्म ‘मैन ऑन ए मिशन’ की कहानी है, जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए हर हद से ऊपर चला जाता है।

वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे अजय देवगन

वहीं आज यानि 17 मार्च को अजय देवगन अपनी फिल्म के प्रमोशन और भारतीय क्रिकेट टीम को अपना समर्थन देने के लिए

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के मिशन पर हैं। इसलिए वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे विश्व कप के मैच में शामिल होंगे। फिल्म को यहां प्रमोट करने की वजह ये है कि जैसे भोला अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी मुश्किलों को पार कर लेता है, वैसे ही हमारी भारतीय टीम कभी हार नहीं मानती है और देश के लिए अपने प्यार के लिए हर मुश्किल से आखिर तक लड़ती है।

30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म

फिल्म ‘भोला’ साल 2019 की तमिल फिल्म ‘कैथी’ का रिमेक है। जिसमें अजय देवगन के साथ, तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा और गजराज राव जैसे दिग्गज कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इसके अलावा साउथ स्टार अमाला पॉल और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन भी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। बता दें कि अजय की ये फिल्म ‘भोला’ 30 मार्च 2023 को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है।

आठवें वेतन आयोग का गठन की हो रही मांग, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लेंगे फैसला



मुंबई: आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाना चाहिए, यह बात केंद्रीय कर्मचारियों के संघ लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं। यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा।

अमूमन हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग के गठन के माध्यम से वेतन में टोस बढ़ोतरी का मौका मिलता है। सरकार इस प्रकार के आयोग के गठन के साथ कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा आरंभ करती ताकि अलग-अलग परिस्थिति में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाए और काम के अनुसार भत्तों को तय किया जाए। बता दें कि पिछले वेतन आयोग

के लागू होने के बाद भी कई केंद्रीय कर्मचारियों में न्यूनतम वेतनमान को लेकर असंतोष बरकरार रहा और वे काफी समय तक इस प्रयास में रहे कि सरकार उनकी मांगों को मान लें। लेकिन अंततः ऐसा नहीं हो पाया था। यह अलग बात है कि बीच-बीच में सरकार की ओर से कुछ मांगों को बाद में स्वीकार भी किया गया था।

7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर एमएसीपी को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्वीकारना बना था। बता दें कि इससे खास तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी।

जानकारी दे दें कि सातवें वेतन आयोग से पहले 7000 रुपये न्यूनतम वेतनमान हुआ करता था। जबकि लागू होने के बाद इसे 18000 रुपये कर दिया गया। तब सरकारी कर्मचारियों की यूनिनन इसे 26000 करने की मांग कर रही थीं। जबकि एक समय आया था (सूत्रों के हवाले से जानकारी) कि सरकार इसे 21000 करने पर तैयार हो गई थी, लेकिन यह बात केवल चर्चाओं में रही और कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं थे।

बेमौसम की बरसात के कारण हजारों एकड़ की फसलें हुईं नष्ट!



मुंबई: इन दिनों किसान एक तरफ अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलने से परेशान हैं तो दूसरी तरफ बेमौसम की बारिश से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। आम का मौसम आ चुका है, पर प्राकृतिक आपदा और बेमौसम की बरसात के कारण इस बार लगता है कि आम लोगों तक यह 'आम' नहीं पहुंच पाएगा। आम के काफी फल बर्बाद हो गए हैं। बेमौसम की इस बरसात ने इस हापुस को भी 'खास' फल बना दिया है।

बता दें कि मुंबई से सटे पालघर में काफी बड़ी संख्या में किसान खेती करते हैं। इनमें फल व सब्जियों की खेती प्रमुख है। बेमौसम की बरसात में फल व सब्जियों की बड़ी मात्रा नष्ट हो गई है। इससे इन फलों व सब्जियों के दाम महंगे हो जाएंगे।

पालघर में बड़ी संख्या में मिर्च व शिमला मिर्च की खेती की गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम की बरसात से पालघर जिले के ५४१ गांवों के हजारों किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर खराब हुई हैं। आम के वृक्षों पर लगे छोटे आकार के आम बारिश के कारण पेड़ों से नीचे गिर गए हैं। इसके चलते आम बगान के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान गणपत पाटील ने बताया कि उन्होंने अपने दो एकड़ में सब्जियों की खेती की थी, लेकिन बारिश से सब्जी की पूरी फसल चौपट हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बेमौसम बारिश के कारण लगभग २,११७.४८ हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है और करीब ८,८३६ किसान प्रभावित हुए हैं।

सड़क का विकास कार्य १० वर्षों से लटका रहा, दुर्घटनाओं में २,५०० लोगों की मौत

मुंबई: अक्सर खराब सड़कों के कारण देश में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ज्यादातर उबड़-खाबड़ सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसी घातक सड़कों की जानकारी होने के बाद भी प्रशासन की ओर से तत्परता न दिखाना लापरवाही की श्रेणी में आता है और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम जनता भुगतती है। ऐसा ही एक उदाहरण महाराष्ट्र गोवा हाईवे पर देखने को मिला है। जहां १०५ किमी सड़क का विकास कार्य पिछले १० वर्षों से लटका रहा और इस बीच इस सड़क पर अलग-अलग दुर्घटनाओं में २,५०० लोगों की मौत हो गई। साफ कहें तो प्रशासन की १० साल की लेटलतीफी के चलते २,५०० लोगों की जानें गई हैं। आखिर, इन हादसों और मासूम लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। हाल ही में यह मामला सदन से लेकर सड़क तक उठा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महानगर मुंबई को गोवा से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे के निर्माण प्रोजेक्ट पर काम शुरू है। मुंबई और गोवा के बीच राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-६६ है। इसके निर्माण कार्य को १२ साल



पहले शुरू किया गया था। केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग ने ३५५ किमी लंबे इस महामार्ग की २५० किमी सड़क का विकास किया था लेकिन १०५ किमी सड़क का विकास काम

शेष रह गया। ऐसा लगता है जैसे सरकार द्वारा उसे भुला दिया गया है। इस आधे-अधूरे हाईवे के पुनर्निर्माण के कारण पिछले १० वर्षों (जनवरी २०१० से अप्रैल २०२१) में लगभग

२,५०० लोगों की विभिन्न दुर्घटनाओं में मौत हो गई तो लगभग ३ हजार लोग घायल हो चुके हैं। वहीं कई स्थानीय निवासी विकलांगता के शिकार हुए हैं। मुंबई-गोवा हाईवे को कोंकण वासियों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इस महामार्ग पर एनएच-६६ कुल ३५५ किमी लंबा है। इसमें वर्ष २०१० से कुछ वर्षों तक २५५ किमी सड़क का पुनर्विकास हो सका, बाकी १०५ किमी सड़क का पुनर्विकास लटका रहा।

शहर में फ्लू के 118 मामले सामने आए, घर-घर कर रही सर्वेक्षण मनपा

मुंबई: मुंबई पर H3N2 का संकट गहरा गया है। बीते कई दिनों से इस विषाणु के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जनवरी से १५ मार्च यानी बुधवार तक शहर में फ्लू के ११८ मामले सामने आए हैं। वहीं शहर में तेजी से रोगियों की बढ़ती संख्या को देखकर अभी तक चिर निद्रा में सोई मनपा हरकत में आ गई है। इसके तहत मनपा का स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मचारियों की मदद से मुंबई में घर-घर सर्वेक्षण कर खासकर बुखार से पीड़ित मरीजों और जिन्हें वायरल इन्फेक्शन का खतरा है ऐसे



रोगियों की तलाश रहा है। इसके साथ ही उनकी भी खोजबीन की जा रही है, जिन्होंने इलाज नहीं कराया है।

कोरोना काल में राज्य और शहर के पिछले अनुभव को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसके तहत ही मनपा प्रशासन घर-घर जाकर मरीजों

को ढूँढ़ने का प्रयास कर रहा है। ज्ञात हो कि मुंबई में जनवरी से १५ मार्च २०२३ तक लगभग ११८ H3N2 मामले सामने आए हैं।

इनमें जनवरी में ११, फरवरी में ४६ और मार्च में ५३ मामले स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज किए। कुल मरीजों में से ३२ मरीजों का शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल मरीजों में से चार मरीज H3N2 और २८ मरीज एच१एन१ वायरस से संक्रमित हैं। सभी का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।

दो महीने, ८७५ मामलों में ९०० किलो से अधिक सोना जब्त

मुंबई: जुर्म की दुनिया में सोने की तस्करी बहुत पुराना विषय है। पिछले कई सालों में तस्करी के नए-नए तरीके इजाद रहे हैं। सोने की तस्करी बढ़ रही है। मुंबई राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने वर्ष २०२३ के पहले दो महीने में ही ८७५ मामलों में ९०० किलो से अधिक सोना जब्त किया है। यह आंकड़ा वर्ष २०२१ और २०२२ की तुलना में अधिक है। वर्ष २०२० के पूरे वर्ष में यह आंकड़ा ३६ प्रतिशत अधिक है जबकि २०२२ की तुलना में २२ प्रतिशत अधिक है। इसमें सर्वाधिक सोना केरल से बरामद किया गया है। यह तस्करी कर सोना सबसे अधिक म्यांमार के रास्ते लाते हुए पाया गया है। एक समय ऐसा था,



जब लोग अपने शरीर पर सोना पहन कर या सामान में छुपा कर लाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्करी के कई अजीबोगरीब तरीके सामने आए हैं जिसने पुलिस को अचंभे में डाल दिया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिए रिपोर्ट में बताया है कि इस वर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान सोने की तस्करी के ८७५ मामलों में ९०० किलो से अधिक सोना जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि २०२० में २,५६७, २०२१

में २,४४५ और २०२२ में ३९,८२ किलो सोना जब्त किया गया। मात्र २०२० में जब्त किया गया कुल सोना २,१५४.५८ किलोग्राम था, जो २०२१ में बढ़कर २,३८३.३ किलोग्राम और २०२२ में ३,५०२.१६ किलोग्राम हो गया। वहीं दूसरी ओर २०२३ के पहले दो महीने में ९१६ किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया गया है। इस व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि तस्करी बढ़ने की एक और वजह सीमा शुल्क में बढ़ोतरी है। वर्ल्ड गोल्ड कार्सिल (डब्ल्यूजीसी) के अनुसार सोने पर आयात शुल्क में ७.५ प्रतिशत से १२.५ प्रतिशत की वृद्धि के कारण तस्करी कोविड से पहले की तुलना में २०२२ में ३३ प्रतिशत तक बढ़ी है।

शिक्षा पर भी महंगाई की मार

अभिभावक परेशान



मुंबई, केंद्र सरकार का गलत नीति के चलते अब शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। कॉपी, किताब और स्टेशनरी सामग्री की कीमतों में ३० से ४० फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जून में स्कूल का नया सत्र शुरू होने पर

फीस, कॉपी, किताब और अन्य चीजों की बढ़ी कीमतों का बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ता दिखाई देगा। महंगाई अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रही है। अभिभावकों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्कूल फीस बढ़ने के साथ ही यूनिफार्म, जूते-मोजे व कॉपी-किताबें भी महंगी हो गई हैं। दाम में करीब २५ से ३० फीसदी तक बढ़ोतरी

हुई है। इससे अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों की मानें तो ब्रांडेड स्कूल बैग पहले जहां २०० से ३०० रुपए में मिल जाता था, अब वही बैग ४०० रुपए तक मिलने लगा है। प्लास्टिक के सामान जैसे बॉटल, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स आदि में भी १० से लेकर २० रुपए तक की वृद्धि हुई है। कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों में फेरबदल करने से नई किताबों की रेट काफी अधिक है। इसी के साथ कॉपी, पेंसिल, पेन, रबर, स्याही आदि के भाव में भी करीब १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बेमौसम की बारिश! राज्य के ४ जिलों में ऑरेंज अलर्ट



मुंबई : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल राज्य के ४ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पुणे, नगर, छत्रपति संभाजीनगर और जलगांव जिले शामिल हैं। इस दौरान

तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी। मुंबई से गढ़चिरोली और कोल्हापुर से नंदुरबार जिले में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पालघर, वर्धा, नागपुर, भंडारा और गढ़चिरोली जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर-मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के कई जिलों में अगले ५ दिनों में गरज के साथ बारिश होगी।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई, ठाणे, पूरे विदर्भ, पुणे और घाट क्षेत्र में बारिश होगी। दरअसल, मुंबई समेत कई उपनगरों में कल सुबह से ही बूदाबूदा हो रही है। मुंबई उपनगर के दहिसर, बोरीवली इलाके में कल रात से रुक-रुक कर बूदाबूदा हो रही है। ठाणे, दिवा, डॉबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर और ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार सुबह से बूदाबूदा शुरू हो गई। इससे काम पर जानेवाले मजदूरों

की संख्या में कमी आई है। इस बीच पिछले २४ घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

महानगर मुंबई में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और कल कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल छाए रहने से तापमान में भारी गिरावट देखी गई। इस बेमौसम बारिश ने फरवरी महीने से ही गर्मी से झुलस रहे मुंबईकरों को काफी हद तक राहत दी है।



बिकिनी को लेकर ट्रेलर्स के निशाने पर आई मौनी रॉय, बॉडी शेमिंग के बाद तुरंत डिलीट किया वीडियो



मुंबई : नागिन फेम मौनी रॉय सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों के कारण अक्सर चर्चा बटोरती हैं। बीच से लेकर पार्टी तक, एक्ट्रेस अपना लगभग हर लुक फैंस के साथ शेयर करती हैं।

बोल्डनेस से फैंस को घायल करती मौनी

मौनी रॉय इन दिनों मियामी में वेकेशन मना रही हैं। जहां से उन्होंने अब तक अपनी कई बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं और हर बार फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराई हैं, लेकिन बीते दिन मौनी बोल्डनेस के चक्कर में ट्रेलर्स के हत्ये चढ़ गईं।

वेकेशन मना रही मौनी

मौनी रॉय ने गुरुवार को मियामी से अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें एक्ट्रेस प्रिंटेड बिकिनी पहने सड़क पर ड्रांस करते हुए नजर आ रही थीं। मौनी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया एक्ट्रेस की बुरी तरह ट्रेलिंग शुरू हो गई।

वीडियो को लेकर ट्रेल हुई एक्ट्रेस

मौनी अपने वीडियो में मियामी बीच पर बिकिनी पहने कातिलाना अंदाज में फोटोशूट कर रही थीं। मियामी के सड़कों पर मौनी का बिंदसा होकर नाचना कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक्ट्रेस को संस्कृति की याद दिलाते हुए भला बुरा कहना शुरू कर दिया।

बाथरूम में गिरी मां, चोट की वजह से 2 दिन बाद मर गई... बेटी ने कहा- मैं डर गई तो काट डाला

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लालबाग चॉल में एक महिला की हत्या के मामले में अहम खुलासा हुआ है। यह वारदात मृत महिला की सगी बेटी ने अंजाम दिया है। इस वारदात में उसके पड़ोस में रहने वाले एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करने वाले दो वेटरों ने सहयोग किया था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस वारदात के पीछे आरोपी लड़की की मंशा क्या थी। फिलहाल मुंबई पुलिस वारदात में सहयोग करने वाले दोनों वेटरों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी मां की हत्या करने के बाद शव के पांच टुकड़े किए और पॉलिथीन में लपेट कर आलमारी और पानी के ड्रम में डाल दिया था। यह वारदात करीब ढाई महीने पहले की है। आरोपी लड़की की पहचान रिपल



आरोपी लड़की ने बताया कि इस घटना के बाद वह डर गई थी और डर के मारे ही उसने शव के टुकड़े किए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की ने मार्बल कटर से अपनी मां के शव को पांच टुकड़ों में काट दिया था। चूंकि यह काम वह अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने पड़ोस में रहने वाले दोनों वेटरों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस की अलग टीमें इन दोनों वेटरों की तलाश में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंची हैं।

जैन के रूप में हुई है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसकी मां बाथरूम जाते समय गिर गई थी। इससे उसे चोट लगी और चोट की वजह से ही पिछले साल 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को इन दोनों वेटरों के

आरोपी की कहानी से सहमत नहीं पुलिस

वहीं आरोपी रिपल ने पुलिस को दिए कबूलनामे में बताया कि वह 55 वर्षीय अपनी मां को टॉयलेट ले जा रही थी। इसी दौरान वह सीढ़ियों पर फिसल गई और बुरी तरह से चोटिल हो गई। ऐसे में उसने पड़ोस में रहने वाले दोनों वेटरों को मदद के लिए बुलाया और अपने घर ले आईं। लेकिन इस चोट की वजह से कुछ घंटे बाद ही उसकी मां की मौत हो गई। इससे वह डर गई और दो दिन बाद उसने शव के टुकड़े करने का फैसला किया था। हालांकि पुलिस उसके इस बयान से सहमत नहीं है।

है कि मौत से पहले उसे बुरी तरह से टार्चर किया गया था, वहीं मौत के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. राजेश डेरे के मुताबिक यह साफ तौर पर हत्या का मामला है।

स्कूल की कक्षा में सांप के घुसने से शिक्षकों और छात्रों में दहशत, सर्प मित्र मौके पर



कल्याण : कल्याण पश्चिम के लाल चौकी परिसर स्थित एक स्कूल में सांप घुसने से छात्र-छात्राओं में भय व्याप्त हो गया। बुधवार को यह घटना उस समय हुई जब आठवीं कक्षा के एक शिक्षक ने लंबे सांप को देखा और डर गया। प्रधानाध्यापिका वैशाली पाटिल ने सांप मित्र दत्ता बॉम्बे से संपर्क किया और बताया कि क्लास में एक सांप है। फौरन सपेरे दत्ता बॉम्बे स्कूल पहुंचे और साढ़े पांच फुट लंबी धामिन सांप को कक्षा में पकड़ लिया और उपस्थित शिक्षकों और छात्रों ने संतोष की सांस ली, यह धामिन प्रजाति का सांप है, जिसे सपेरे दत्ता बॉम्बे ने जीवन दिया। दत्ता ने कहा कि यह जहरीला नहीं है और चूहों को अपना शिकार बनाता है।

ट्रक का पल्ला तोड़ अंदर घुस गई कार, 3 और जिंदगियों के लिए काल बना मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे



मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे में एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। उस गांव के टोल नाके के पास एक खड़ी हुई ट्रक के पीछे से तेज रफ्तार में आती हुई कार ने टक्कर मार दी। कार में एक चालक और दो अन्य लोग सवार थे। इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार तीनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। यह कार मुंबई से पुणे की दिशा में जा रही थी। कार और ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि आधी कार बिलकुल ट्रक के अंदर चली गई। दुर्घटना के कुछ वक्त तक ट्रैफिक जाम हो गया। इसके बाद महामार्ग पुलिस ने क्रेन की

मदद से वाहनों को सड़क के किनारे लगाया तो ट्रैफिक शुरू हो सका। लेकिन इस भीषण दुर्घटना से फिर एक बार यह सवाल खड़ा हुआ कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं?

क्यों, कैसे, कब, कहां हुई दुर्घटना ?

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उस गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तलेगांव टोल नाके के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ी थी। तभी मुंबई से पुणे की दिशा में जा रही एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक के पीछे से आकर टक्कर मार दी। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि आधी

कार बिलकुल ट्रक के अंदर चली गई। इस कार में एक चालक समेत तीन लोग सवार थे। उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने जांच शुरू की, मृतकों का अता-पता जानने की कोशिश

अब तक मरने वाले लोगों की पहचान नहीं तय हो पाई है। वे कहां के रहने वाले थे, यह जानकारी सामने नहीं आ पाई है। एक शख्स के बारे में पता चला है कि उनका नाम विजय विश्वनाथ खैरे था और वे सातारा का रहने वाले थे। यह हादसा सुबह करीब साढ़े सात से आठ बजे के बीच हुआ। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक ट्रक खराब हो गई थी। इसलिए ड्राइवर ने इसे सड़क किनारे खड़ी कर दिया था। पीछे से तेज रफ्तार से आती हुई कार ने इसे टक्कर मार दी। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि कार चालक ने किस वजह से नियंत्रण खो दिया।

जल्द वसई-विरार में चलेगी 61 नई इलेक्ट्रिक बसें



विरार : वसई-विरार महानगरपालिका ने शहर में परिवहन सेवाओं में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। परिवहन सेवा के सहायक आयुक्त विश्वनाथ तलेकर ने कहा कि वसई-विरार में जल्द ही 61 नई इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। जिससे यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। वसई-विरार महानगरपालिका परिवहन सेवा में 32 रूटों पर मात्र 103 बसें चल रही हैं। बसों की संख्या कम होने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। यहां ऑटो चालक बसों के नहीं होने का फायदा उठाते हैं और यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। लंबे समय से लोगों की मांग के बाद महानगरपालिका ने राज्य सरकार

से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। होगी महानगरपालिका के पैसे की बचत और कम होगा प्रदूषण तलेकर ने कहा कि अप्रैल तक नई बसें आने की संभावना है। बसों की संख्या कम होने के कारण यहां अवैध रिक्शों की संख्या बढ़ती जा रही है। नई बसों के आने से अवैध रिक्शा पर अंकुश लगेगा और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। इसका लाभ आने वाले समय में आम लोगों को मिलेगा। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के आने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही डीजल और पेट्रोल का खर्च भी बचेगा। हर सेक्शन और डिपो में बसों के लिए चार्जर स्टेशन बनाए जाएंगे।